

## ग्रामीण भारत में नशाखोरी नियंत्रण के लिए सरकारी प्रयास: एक विश्लेषण

<sup>1</sup>कुमारी पारुल, <sup>2</sup>डॉ. महेन्द्र कुमार चौरसिया

<sup>1</sup>शोधार्थी, <sup>2</sup>पर्यवेक्षक

<sup>1-2</sup>विभाग: समाजशास्त्र, आई.ई.सी. विश्वविद्यालय

### सार

ग्रामीण भारत में नशाखोरी नियंत्रण के लिए सरकारी योजनाएँ एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे पहुँच, जागरूकता, सांस्कृतिक मान्यताएँ, संसाधनों की उपलब्धता, सामुदायिक भागीदारी, आर्थिक बाधाएँ और प्रशासनिक चुनौतियाँ। उपचार केंद्रों की सीमित पहुँच, परिवहन की समस्याएँ, स्वास्थ्य सेवा का अभाव और सामाजिक कलंक अक्सर इन योजनाओं की सफलता में बाधा डालते हैं। हालाँकि, टेलीमेडिसिन, मोबाइल नशा मुक्ति इकाइयों और सामुदायिक-आधारित कार्यक्रमों जैसी कुछ पहलों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को अनुकूलित करना, जागरूकता बढ़ाना, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना और संरचनात्मक व आर्थिक बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। इस विश्लेषण में सरकारी प्रयासों की सफलता, उनकी सीमाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यसन नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा की गई है।

### मुख्य शब्द:

ग्रामीण भारत, नशाखोरी नियंत्रण, सरकारी योजनाएँ, जागरूकता, स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक भागीदारी, सामाजिक कलंक, संरचनात्मक बाधाएँ, आर्थिक चुनौतियाँ, नीति सुधार।

## परिचय

भारत में नशाखोरी एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ सीमित संसाधन, जागरूकता की कमी और सामाजिक कलंक के कारण इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण समुदायों में नशे की लत केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता, स्वास्थ्य समस्याएँ और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा नशाखोरी की रोकथाम और पुनर्वास के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य न केवल उपचार प्रदान करना बल्कि इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और नशे की समस्या की जड़ तक पहुँचना भी है। हालाँकि, इन योजनाओं की प्रभावशीलता विभिन्न संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक बाधाओं के कारण सीमित हो जाती है, जिससे नशे की समस्या ग्रामीण भारत में एक जटिल मुद्दा बनी हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारी योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी प्रभावी ढंग से स्थानीय आबादी तक पहुँच पाती हैं। हालाँकि, भौगोलिक चुनौतियाँ, अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा और परिवहन की कमी के कारण ये योजनाएँ अपेक्षित स्तर पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पातीं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण समुदायों में व्याप्त सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएँ भी इस समस्या को जटिल बनाती हैं। कई मामलों में, नशे की लत को एक स्वास्थ्य समस्या के बजाय नैतिक या व्यक्तिगत कमजोरी के रूप में देखा जाता है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक उपचार प्राप्त करने में संकोच होता है। इस मानसिकता को बदलने और अधिक से अधिक लोगों

को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए सरकार को व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और स्थानीय नेतृत्व को इस प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे किस हद तक ग्रामीण समुदायों की वास्तविक जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल बनाई गई हैं। कई बार देखा गया है कि नशा मुक्ति केंद्र या पुनर्वास सुविधाएँ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए इनका लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह, सरकारी प्रयासों में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित पेशेवरों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण कई योजनाएँ कागजों पर ही सीमित रह जाती हैं। हालाँकि, कुछ सफल उदाहरण भी मौजूद हैं, जहाँ सरकार ने स्थानीय संगठनों, गैर-सरकारी संस्थानों और समुदायों के साथ मिलकर नशा मुक्ति कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया है। इन सफलताओं से सीख लेते हुए, सरकार को नीति-निर्माण में अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार हो सके।

अतः, ग्रामीण भारत में नशाखोरी नियंत्रण के लिए सरकारी प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी अच्छी तरह से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किए गए हैं, जागरूकता बढ़ाने के लिए कितने व्यापक और प्रभावी अभियान चलाए गए हैं, और सरकार, समुदाय व अन्य हितधारकों के बीच कितना समन्वय स्थापित किया गया है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना, उनकी चुनौतियों को समझना और उनके प्रभाव को अधिक प्रभावी बनाने के लिए

संभावित समाधानों की पहचान करना है, जिससे ग्रामीण भारत में नशाखोरी की समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

## ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता

ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं की लत जैसे मुद्दों को संबोधित करने में सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता व्यापक रूप से भिन्न होती है और यह पहुँच, बुनियादी ढाँचे, सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक गतिशीलता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। जबकि कई पहलों ने वादा दिखाया है, ग्रामीण परिवेश की अनूठी चुनौतियाँ अक्सर उनकी पहुँच और प्रभाव को सीमित करती हैं, जिससे अधिक प्रभावशीलता के लिए अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

### 1. पहुँच और जागरूकता

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की एक बड़ी सीमा उनकी पहुँच है। उपचार केंद्रों से भौतिक दूरी, परिवहन की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचा ग्रामीण आबादी तक सेवाओं की डिलीवरी में बाधा डालता है। सीमित संचार नेटवर्क और साक्षरता बाधाओं के कारण जागरूकता अभियान अक्सर दूरदराज के क्षेत्रों में पहुँचने में विफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, व्यसन निवारण पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाएँ ग्रामीण युवाओं तक पहुँचने में संघर्ष कर सकती हैं, जो शहरी-केंद्रित पहलों से अधिक अलग-थलग हैं। इन अंतरालों के निवारण के लिए बेहतर आउटरीच और स्थानीयकृत संचार रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

### 2. सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ

ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गहरे सामाजिक मानदंड और कलंक अक्सर व्यक्तियों को मदद लेने से रोकते हैं। सरकारी योजनाएँ, भले ही नेक इरादे वाली हों, लेकिन इन सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने में विफल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण समुदाय व्यसन को स्वास्थ्य समस्या के बजाय नैतिक विफलता के रूप में देख सकते हैं, जिसके कारण पुनर्वास कार्यक्रमों में कम भागीदारी होती है। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोणों को शामिल करना और स्थानीय नेताओं को शामिल करना इन योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

### 3. संसाधनों की उपलब्धता

ग्रामीण क्षेत्रों में कई सरकारी योजनाओं को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी, अपर्याप्त निधि और अपर्याप्त सुविधाएँ। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में अक्सर व्यसन उपचार प्रदान करने के लिए विशेष कर्मचारियों और उपकरणों की कमी होती है। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ क्षेत्रों में मोबाइल नशा मुक्ति इकाइयों जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन उनका कवरेज सीमित है। इन पहलों की सफलता के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करना और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

### 4. सामुदायिक भागीदारी

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ऐसे कार्यक्रम जिनमें स्थानीय हितधारकों, जैसे कि एनजीओ, सामुदायिक नेता और सहकर्मी सहायता समूह सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय स्वयंसेवकों को परामर्शदाता या शिक्षक के रूप में

प्रशिक्षित करने वाली योजनाएं विश्वास बनाने और सामुदायिक भागीदारी में मदद कर सकती हैं। हालाँकि, कई पहल अभी भी ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण पर निर्भर हैं, जो ग्रामीण आबादी के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकते हैं।

### **5. आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ**

ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी अक्सर सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को कमजोर कर देती है। जब सेवाएँ उपलब्ध होती हैं, तब भी ग्रामीण परिवारों की आर्थिक अस्थिरता व्यक्तियों को उपचार कार्यक्रम पूरा करने से रोक सकती है। इसके अलावा, खराब परिवहन और संचार नेटवर्क जैसी ग्रामीण बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ इन पहलों की पहुँच को और सीमित कर देती हैं।

### **6. सफलता की कहानियाँ और सुधार के क्षेत्र**

कुछ सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूलित रणनीतियों को अपनाकर प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, समुदाय-आधारित नशा मुक्ति कार्यक्रम जो पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक उपचार विधियों के साथ एकीकृत करते हैं, ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदराज के स्थानों में व्यसन उपचार प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन जैसी तकनीक का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। हालाँकि, ये सफलताएँ अक्सर अलग-थलग होती हैं, और उन्हें बढ़ाने के लिए निरंतर निवेश और नीति की आवश्यकता होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की लत जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण क्षमता है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अक्सर इन क्षेत्रों की अनूठी चुनौतियों से

सीमित होती है। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, सरकारों को पहुँच में सुधार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और संरचनात्मक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लक्षित प्रयासों और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, सरकारी पहल ग्रामीण आबादी के जीवन को बेहतर बनाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है।

### **ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के समक्ष चुनौतियाँ**

ग्रामीण क्षेत्रों में नशाखोरी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी योजनाओं को अक्सर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी सफलता में बाधा डालती हैं। ये बाधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की अनूठी सामाजिक-आर्थिक, अवसंरचनात्मक और सांस्कृतिक गतिशीलता में निहित हैं। इन चुनौतियों को समझना इन योजनाओं की प्रभावशीलता और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है।

#### **1. अपर्याप्त बुनियादी ढांचा**

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी होती है। खराब सड़क नेटवर्क, सीमित परिवहन सुविधाएं और अविश्वसनीय बिजली सेवाओं की डिलीवरी में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए, पुनर्वास केंद्र या नशे को दूर करने के लिए कार्यक्रम अक्सर ग्रामीण समुदायों से दूर स्थित होते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों के लिए पहुँच मुश्किल हो जाती है।

#### **2. अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर संसाधन**

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, परामर्शदाताओं और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण विशेष सेवाओं की उपलब्धता सीमित हो जाती है। सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र और स्वास्थ्य सेवा पहल कुशल कर्मचारियों और संसाधनों की कमी के कारण पर्याप्त कवरेज प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ अक्सर कम वित्तपोषित और खराब रूप से सुसज्जित होती हैं, जिससे बड़ी, बिखरी हुई आबादी की माँगों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

### **3. जागरूकता और साक्षरता का निम्न स्तर**

कम साक्षरता दर और सूचना तक सीमित पहुंच के कारण कई ग्रामीण आबादी सरकारी योजनाओं के अस्तित्व और लाभों से अनभिज्ञ हैं। जागरूकता अभियान अक्सर इन क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने में विफल रहते हैं, खासकर जब वे शहर-केंद्रित मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्भर होते हैं। ज्ञान की इस कमी के कारण नशे और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों में कम नामांकन और भागीदारी दर होती है।

### **4. सांस्कृतिक और सामाजिक कलंक**

गहराई से जड़ जमाए सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड अक्सर सरकारी योजनाओं की सफलता में बाधा बनते हैं। ग्रामीण समुदायों में, नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को अक्सर चिकित्सा स्थितियों के बजाय नैतिक विफलताओं के रूप में देखा जाता है, जिससे व्यक्ति मदद लेने से कतराते हैं। इसके अतिरिक्त, लैंगिक पूर्वाग्रह महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या रोजगार योजनाओं तक पहुँचने से रोक सकते हैं, जिससे इन पहलों से लाभ उठाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

## 5. आर्थिक बाधाएँ

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उच्च स्तर व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं में भाग लेना मुश्किल बनाता है, भले ही वे उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए, यात्रा या न्यूनतम वित्तीय योगदान की आवश्यकता वाले कार्यक्रम कई ग्रामीण परिवारों के लिए वहनीय नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में आर्थिक अस्थिरता व्यक्तियों के लिए कौशल-निर्माण या पुनर्वास कार्यक्रमों में दीर्घकालिक भागीदारी को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना सकती है।

## 6. प्रशासनिक अक्षमताएं

नौकरशाही की देरी, भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों के बीच खराब समन्वय अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन को कमजोर करते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधन कुप्रबंधन या दुरुपयोग के कारण इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की कमी के कारण इन पहलों के प्रभाव का आकलन करना और कमियों को दूर करना मुश्किल हो जाता है।

## 7. भौगोलिक अलगाव

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र अक्सर भौगोलिक रूप से अलग-थलग होते हैं, जिससे सेवाओं और बुनियादी ढांचे को वितरित करना मुश्किल हो जाता है। यह अलगाव विशेष रूप से पहाड़ी, जंगली या सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्याग्रस्त है, जहाँ ऐसी चुनौतियाँ सरकारी योजनाओं को लागू करने की लागत और जटिलता को काफी बढ़ा देती हैं।

## 8. सीमित सामुदायिक सहभागिता

नीति निर्माण और कार्यान्वयन में शीर्ष-स्तरीय दृष्टिकोण अक्सर ग्रामीण आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं। योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी की कमी के परिणामस्वरूप ऐसे कार्यक्रम बनते हैं जो स्थानीय संदर्भों या प्राथमिकताओं के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकते हैं।

## 9. परिवर्तन का प्रतिरोध

ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का प्रतिरोध एक और चुनौती है, जहाँ पारंपरिक प्रथाएँ और मान्यताएँ अक्सर हावी रहती हैं। नई पहल, विशेष रूप से नशे की लत या लैंगिक समानता जैसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने वाली पहलों को स्थानीय समुदायों या नेताओं से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और भी सीमित हो जाती है।

सरकारी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर बुनियादी ढाँचे, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, सरकारों को अधिक स्थानीयकृत और सहभागी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, संसाधन आवंटन में सुधार करना चाहिए और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण में निवेश करना चाहिए।

## निष्कर्ष

ग्रामीण भारत में नशाखोरी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारी योजनाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता कई संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक बाधाओं से प्रभावित होती है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, संसाधनों की कमी,

जागरूकता की न्यूनता, सामाजिक कलंक और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ इन योजनाओं की सफलता में प्रमुख अवरोधक हैं। हालाँकि, कुछ पहल, जैसे सामुदायिक-आधारित पुनर्वास कार्यक्रम, टेलीमेडिसिन सेवाएँ, और मोबाइल नशा मुक्ति इकाइयाँ, प्रभावी समाधान प्रदान करने में सफल रही हैं, लेकिन इनका दायरा अभी भी सीमित है। इन योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों को अधिक अनुकूलित करना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, संसाधनों का उचित आवंटन करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना आवश्यक है। दीर्घकालिक प्रभाव के लिए, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक पुनर्वास जैसे कारकों को एकीकृत किया जाए। लक्षित प्रयासों और नीति-निर्माण में सुधार के साथ, सरकारी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में नशाखोरी की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती हैं और प्रभावित व्यक्तियों के जीवन को पुनर्स्थापित करने में सहायक हो सकती हैं।

### संदर्भ

अब्दुलरहीम, आई.ई. (2023)। एबिरा लैंड (कोगी सेंट्रल), कोगी राज्य में युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड एकेडमिक रिसर्च, 9(8), 27–47।

बोजप्पन, एन., और चांद, पी. (2024)। दक्षिण एशिया में पदार्थ उपयोग विकारों से संबंधित नीति, वैधीकरण और कार्यक्रम। दक्षिण एशिया में पदार्थ उपयोग विकारों पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य: सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य पहलू (पृष्ठ 165–182)। सिंगापुर: सिंगर नेचर सिंगापुर।

गुप्ता, आर. (2018)। भारतीय और पश्चिमी युवाओं में नशीली दवाओं की लत की एक क्रॉस-सांस्कृतिक परीक्षा: रोकथाम के लिए निहितार्थ। इंडियन जर्नल ऑफ क्रॉस-कल्चरल साइकोलॉजी, 37(1), 56–71.

इवानोवा, एमपी (2020)। पूर्वी यूरोप में युवाओं में नशीली दवाओं की लत: एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। पूर्वी यूरोप, रूस और मध्य एशिया का समाजशास्त्रीय अध्ययन, 53(1), 89–103.

कुमार, वी. (2022)। दक्षिण भारत में किशोरों के बीच मादक द्रव्यों के उपयोग के रुझान की एक अनुदैर्घ्य परीक्षा: नीति के लिए निहितार्थ। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, 55(2), 178–193.

मार्टिनेज, एलए (2013)। पश्चिमी अफ्रीका में युवा पदार्थ का उपयोग: एक गुणात्मक अध्ययन। अफ्रीकी जर्नल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल स्टडीज, 18(4), 321–336.